

पूर्वोत्तर राज्यों में हृदी के खलिफ वरिध प्रदरशन

प्रलिमिस् के लयि:

त्रिभाषा नीति, संवधिान की छठी अनुसूची, भाषा से संबंघति संवैधानिकि प्रावधान, कोठारी आयोग

मेन्स के लयि:

सरकारी नीतियिँ और हस्तकषेप, राज्यों का भाषायी संगठन, कोठारी आयोग, वविधिता में एकता

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में भारत सरकार ने आठ पूर्वोत्तर राज्यों में हृदी को ककषा 10 तक अनविर्य करने का प्रावधान कयिा है ।

- हृदी को 'भारत की भाषा' के रूप में वर्णति कयिा गया है ।
- हालाँकि पूर्वोत्तर के वभिन्नि संगठनों द्वारा इस कदम का वरिध कयिा जा रहा है । साथ ही कई दकषणि भारतीय राज्यों ने केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की है ।
- इसके बजाय ये समूह **त्रिभाषा नीति** अंगरेजी, हृदी और स्थानीय भाषा का समर्थन कर रहे हैं ।

पूर्वोत्तर संगठन द्वारा प्रस्तुत तर्क:

- **छठी अनुसूची:** ये राज्य संवधिान की **छठी अनुसूची** द्वारा संरक्षति हैं, ऐसे में केंद्र सरकार छात्रों पर हृदी भाषा को थोप नहीं सकती है ।
- **भेदभाव:** केंद्र सरकार का यह कदम हृदी भाषियों को आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक बढत प्रदान करेगा और उन्हें दीर्घकाल में देश के गैर-हृदी भाषी कषेत्रों को नयित्तरति करने में सहायता करेगा ।

हृदी भाषा और पहचान की समस्या:

- **राज्यों का भाषायी संगठन:** भारत में अधिकांश राज्यों का गठन भाषायी आधार पर कयिा गया है ।
 - भारत में सीमति संसाधनों के कारण पहचान को लेकर वशिष रूप से भाषाओं को लेकर संघर्ष बढ जाता है ।
- **भाषायी वभिजन के उदाहरण:** भाषा की स्थति एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा रही है, जो कतितीत में राज्यों के वभिजन का कारण बना ।
 - आंध्र प्रदेश (भाषायी आधार पर गठति पहला राज्य), पंजाब और गुजरात जैसे राज्य भाषायी आधार पर राज्य की मांग के कारण बनाए गए थे ।
- **संघर्ष प्रबंधन का साधन:** भाषा नीति एक तरीका है, जिसके द्वारा सरकारें जातीय संघर्ष का प्रबंधन करने का प्रयास करती हैं ।
 - इस प्रकार संघीय सहयोग वकिसति करने के लयि भाषा नीति पर राज्यों की स्वायत्तता त्रिभाषा सूत्र लागू करने की तुलना में अधिक व्यवहार्य वकिल्प हो सकती है ।

त्रिभाषा सूत्र क्या है और इसकी आवश्यकता क्यौं है?

- **परचिय:** त्रिभाषा सूत्र पहली बार **कोठारी आयोग** द्वारा 1968 में प्रस्तावति कयिा गया था । इस योजना के तहत:
 - **पहली भाषा:** यह मातृभाषा या कषेत्रीय भाषा होगी ।
 - **दूसरी भाषा:** हृदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएँ या अंगरेजी होगी । गैर-हृदी भाषी राज्यों में यह हृदी या अंगरेजी होगी ।
 - **तीसरी भाषा:** हृदी भाषी राज्यों में यह अंगरेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी । गैर-हृदी भाषी राज्यों में यह अंगरेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी ।
- **आवश्यकता:** प्राथमिक उद्देश्य बहुभाषावाद और राष्ट्रीय सदभाव को बढावा देना है ।
 - कोठारी समति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक वकिस का एक महत्त्वपूर्ण हस्सा है ।
- **कार्यानवयन:** माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र अपनाना था ।
 - इसमें हृदी भाषी राज्यों में हृदी और अंगरेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन करना शामिल था, अधमिनत: दकषणि

भाषाओं में से एक ।

○ 'गैर-हंदी भाषी राज्यों' में कषेत्रीय भाषा और अंगरेज़ी के साथ-साथ हंदी का अध्ययन कया जाना चाहयि ।

- **कार्यानवयन में समस्या:** हंदी पट्टी के राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश और बहिर में) त्रभाषा सूत्र के तहत दक्षणि भारतीय भाषाओं को शक्तिषण में बढावा नही दे सके ।
 - तमलिनाडु, पुदुचेरी और त्रपुरा जैसे राज्य अपने स्कूली पाठ्यक्रम में हंदी पढाने के लयि तैयार नही थे ।
 - इसके बजाय उन्होंने इस मुद्दे की स्वायत्तता की मांग की ।

भाषाओं से संबधति संवैधानकि प्रावधान क्या हैं?

- **भारत के संवधान का अनुच्छेद 29** अल्पसंख्यकों के हतियों की रक्षा करता है । अनुच्छेद में कहा गया है कनिगरकों के कसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लपि या संस्कृति है, उसे इसे संरक्षति करने का अधिकार होगा ।
- **अनुच्छेद 343 भारत संघ** की आधिकारकि भाषा के बारे में है । इस अनुच्छेद के अनुसार, देवनागरी लपि में हंदी होनी चाहयि और अंकों को भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप का पालन करना चाहयि ।
 - इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है क संवधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंगरेज़ी को आधिकारकि भाषा के रूप में इस्तेमाल कया जाता रहेगा ।
- **अनुच्छेद 346** राज्यों और संघ एवं राज्य के बीच संचार हेतु आधिकारकि भाषा के वषिय में प्रबंध करता है ।
 - अनुच्छेद के अनुसार, उक्त कार्य के लयि "अधिकृत" भाषा का उपयोग कया जाएगा । हालाँकि यदि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हैं क उनके मध्य संचार की भाषा हंदी होगी, तो आधिकारकि भाषा के रूप में हंदी का उपयोग कया जा सकता है ।
- **अनुच्छेद 347** राष्ट्रपति को कसी राज्य की आधिकारकि भाषा के रूप में एक भाषा को चुनने की शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते क राष्ट्रपति संतुष्ट हो क उस राज्य का एक बड़ा हसिसा भाषा को मान्यता देना चाहता है ।
 - ऐसी मान्यता राज्य के कसी हसिसे या पूरे राज्य के लयि हो सकती है ।
- **अनुच्छेद 350A** प्राथमकि स्तर पर मातृभाषा में शक्तिषा की सुवधिएँ प्रदान करता है ।
- **अनुच्छेद 350B** भाषायी अल्पसंख्यकों के लयि एक **वशेष अधिकारी की नयिकृति** का प्रावधान करता है ।
 - **वशेष अधिकारी की नयिकृति राष्ट्रपति** द्वारा की जाएगी, यह भाषायी अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों से संबधति सभी मामलों की जाँच करेगा तथा सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौपेगा ।
 - तत्पश्चात् राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है या उसे संबधति राज्य/राज्यों की सरकारों को भेज सकता है ।
- **अनुच्छेद 351** केंद्र सरकार को हंदी भाषा के विकास के लयि नरिदेश जारी करने की शक्ति देता है ।
- भारतीय संवधान की **आठवीं अनुसूची** में 22 आधिकारकि भाषाओं को सूचीबद्ध कया गया है ।

आगे की राह

- अनेकता में **एकता हमेशा से भारत की ताकत** रही है । इसलयि भाषा से जुड़ी पहचान तथा भारत के एक संघीय राज्य होने के संदर्भ में केंद्र और राज्यों दोनों को **सहकारी मॉडल का पालन** करना चाहयि तथा भाषा **आधिपत्य/अराजकता** से बचना चाहयि ।

स्रोत: द हंदी